रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन): (क) से (ग) गुजरात में यूरिया का कोई कमी नहीं है। जहां तक फास्फेटिक उर्वरकों का सम्बन्ध है, सरकार ने 25.8.1992 से मूल्य एवं संचालन नियंत्रण वापस ले लिया है। तथापि, राज्य में फास्फेटिक उर्वरकों की कुल मिलाकर कोई कमी नहीं है। यूरिया समेत सभी नाइट्रोजनी उर्वरकों की सभी राज्यों में आपूर्ति की उर्वरक विभाग द्वारा निगरानी रखी जाती है और हर राज्य में पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किये जाते हैं। मांग एवं स्वदेशी आपूर्ति के मध्य अन्तर को पूरा करने के लिए आयात करने पड़ते हैं। इसके अलावा डीएपी को अब असरणीबद्ध कर दिया गया है।

(घ) 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी एवं एसएसपी की उपलब्धता ईसीए आवंटन की तुलना में मौसमवार निम्नानुसार थी:—

(आंकड़े लाख मी० टन में)

वर्ष	मौसम	ईसीए आवंटन	उपलब्धता
यूरिया			
1989-90	खरीफ	2.63	3.51
	रबी	3.62	4.15
1990-91	खरीफ	2.91	3.31
	रबी	3.76	4.50
1991-92	खरीफ	2.97	3.60
	रबी	4.16	4.17
डीएपी			
1989-90	खरीफ	1.31	1.77
	रबी	1.89	2.27
1990-91	खरीफ	1.92	2.06
	रबी	1.78	1.79
1991-92	खरीफ	1.97	1.97
	रबी	2.08	2.17
एमओपी			
1989-90	खरीफ	0.31	0.34
	रबी	0.29	0.68
1990-91	खरीफ	0.33	0.42
	रबी	0.40	0.57
1991-92	खरीफ	0.35	0.49
	रबी	0.45	0.45
एसएसपी			
1989-90	खरीफ	0.80*	उपलब्ध नहीं
	रबी	0.74	उपलब्ध नहीं
1990-91	खरीफ	0.66	0.59
	रबी	0.86	0.82
1991-92	खरीफ	0.78	0.69
	रबी	1.06	0.73

सिंगल सुपर फास्फेट जैसे निम्नविश्लेषण उर्वरकों की उपलब्धता की निगरानी केवल 1990-91 में शुरू हुई और इसलिए वर्ष 1989-90 के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

Removal of subsidies on Fertilizer

@3801-F. DR. SANJAYA SINH: SHRI KAMAL MORARKA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Prof. J.K. Galbraith, former United States Ambassador to India has cautioned against the removal of subsidies on fertilizers, as per the news-item entitled: "Agriculture Policy-Galbraith warns against removal of Subsidies", which appeared in the Indian Express dated the 20th November, 1992; and

(b) if so, what are the details thereof and what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) and (b) In the news item referred to in the Question, Prof. J.K. Galbraith is, among other things, reported to have cautioned against the removal of subsidies on fertilizers. He is further reported to have urged against premature action on what has been highly successful agricultural policy.

Nitrogenous fertilizers still continue to be heavily subsidised. In fact, the price of urea has been reduced by 10% *w.e.f.* 25.8.1992, resulting in higher subsidy outgo. However, based on the recommendations of the Joint Parliamentary Committee on Fertilizer Pricing, the import based phosphatic and potassic fertilizers have been de-controlled w.e.f. 25.8.1992. In spite of

@Previously Unstarred Question 3829, transferred from 18th December, 1992.

de-control, farmers are being currently given a subsidy of Rs. 1000 per tonne each on DAP and MOP and proportionate subsidy on complex fertilizers.

Supply of water schemes in U.P.

@3801-G. SHRI ISH DUTT YADAV: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to implement any projects and schemes with the assistance of World Bank or any other International Institution regarding water supply in Azamgarh, Ghazipur, Jaunpur and Sultanpur and Rai Bareli districts of Uttar Pradesh;

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) what is their cost and the year in which they are likely to be completed;

(d) whether there is any delay in the implementation of these projects; and

(e) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) The proposed Project for World Bank assistance would include water supply schemes in Azamgarh, Ghazipur and Jaunpur districts of Uttar Pradesh.

(b) and (c) The proposed project is still at preappraisal/formulation stage. The details and the estimated cost of different components of the project are not available.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

पाकिस्तानी जेलों में भारतीय रक्षा कार्मिक

@@3801-ज. **श्रीमती सत्या बहिनः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस समय पाकिस्तानी जेलों में कुल कितने भारतीय रक्षा कार्मिक बंद हैं;

(ख) क्या दोनों के बीच हाल ही में हुई सचिव स्तर की वार्ता में उनकी रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया था, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार उक्त कैदियों के आश्रितों को कोई राहत देने का विचार रखती है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्वास किया जाता है कि इस समय पाकिस्तान की हिरासत में 54 लापता भारतीय रक्षा कार्मिक हैं।

(ख) और (ग) हालांकि सरकार ने विशिष्ट वर्गों के कैदियों के परिवारों को कुछ सुविधाएं प्रदान की हैं लेकिन पाकिस्तान में बन्दी सभी भारतीय रक्षा कार्मिकों को शीघ्र छुड़ाने और उनके प्रत्यावासन से सम्बद्ध प्रश्न पाकिस्तान सरकार के साथ बार-बार उठाया गया है।

16 से 19 अगस्त, 1992 तक नई दिल्ली में विदेश सचिव स्तर की बातचीत के छठे दौर के दौरान इस मुद्दे पर तकनीकी बातचीत करने पर सहमति हुई थी।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दैनिक मजदूरी की राशि में असमानता

@@@3801-झ. **श्री राम जेठमलानीः**
श्रीमती सुषमा स्वराजः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को दी जाने वाली दैनिक मजदूरी की राशि मात्रा सम्पूर्ण देश में एक समान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो दैनिक मजदूरी की न्यूनतम और अधिकतम राशि कितनी-कितनी है तथा यह किस-किस राज्य में दी जा रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दी जाने वाली दैनिक मजदूरी की यह राशि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार

@Previously Unstarred Question 3970, transferred from 18th December, 1992.

@@पूर्वतः अताराकत प्रश्न 4064, 21 दिसम्बर, 1992 से स्थानान्तरित।

@@@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 4151, 21 दिसम्बर, 1992 से स्थानान्तरित